



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2004/ज्येष्ठ 19, 1926

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2004/JYAISTHA 19, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2004

**विषय :** चीन एवं चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नैरो वोवेन फैब्रिक्स के आयात से सम्बन्धित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

सं. 14/24/2003-डीजीएडी.—मै. स्काई इंडस्ट्रीज लि., मुंबई ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की जिसमें चीन, चीनी ताइपेई तथा हॉंगकाँग के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नैरो वोवेन फैब्रिक्स के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जाँच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।

## 1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान मामले में जाँचाधीन उत्पाद पाइल वीव वाला, मानव निर्मित फाईबरों का बना हुआ तथा बाँधने वाले टेप के रूप में प्रयोज्य नैरो वोवेन फैब्रिक (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। बाजार शब्दावली में संबद्ध वस्तु को " हुक एंड लूप टेप फास्टेनर्स ", " वेल्क्रो टैप्स ", " फास्टेनिंग टेप्स ", " फास्टेनर्स " आदि विभिन्न समानार्थक नामों से जाना जाता है। प्रयोग की जा रही नामावली के बावजूद जाँचाधीन उत्पाद पाइल वीव वाला नैरो वोवेन फैब्रिक है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन विभिन्न आकारों में होता है जो उसके विशिष्ट अंतिम प्रयोग पर निर्भर करते हैं और उन्हें पील स्ट्रेंथ, शीयर स्ट्रेंथ एवं लाइट फास्टनेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। नैरो वोवेन फैब्रिक्स को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

" नैरो वोवेन फैब्रिक्स का अर्थ है (क) दोनों किनारों पर स्लीवेजेस (बुने हुए, चिपकाए हुए अथवा अन्य प्रकार से निर्मित) के प्रावधान सहित 30 से0मी0 से कम चौड़ाई वाले बुने हुए फैब्रिक्स जिन्हें या तो वैसे ही बुना गया हो अथवा चौड़े टुकड़ों में से काटा गया हो; (ख) 30 से0मी0 से कम की सपाट चौड़ाई वाले ट्यूबुलर बुने हुए फैब्रिक्स, और (ग) मुड़े हुए किनारों सहित झुके हुए बंधन जिसकी चौड़ाई जब मुड़ी हुई न हो, तो 30 से0मी0 से अधिक न हो ।"

उपरोक्त परिभाषा से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँचाधीन उत्पाद पूर्ववर्ती विवरण के अनुसार 30 से0मी0 से कम चौड़ाई वाला नैरो वोवेन फैब्रिक है । अध्याय 54 के अंतर्गत विभिन्न सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार चौड़े वोवेन फैब्रिक्स इस जाँच के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं । हुक एवं लूप फास्टेनर्स सामान्य तौर पर मानव निर्मित फाइबर्स (यान्सी), नायलॉन (नायलॉन 6 एवं नायलॉन 6.6), पॉलिस्टर आदि से बनाए जाते हैं । संबद्ध वस्तु दो अलग-अलग बुने हुए टेपों का संयोजन है जिनमें से एक को हुक टेप कहा जाता है और दूसरा लूप टेप कहलाता है जो दूसरे के संपर्क में आने पर उत्कृष्ट बंधन गुण प्रदर्शित करता है । संबद्ध वस्तु से अनुप्रयोजन की विस्तृत शृंखला के लिए सैकड़ों संभावित समापन तंत्रों (बंधन अनुप्रयोजन) का विकल्प मिलता है । संबद्ध वस्तु का मुख्य प्रयोग वस्त्र उद्योग, चर्म वस्त्रों/फर्निशिंग्स, सर्जिकल एवं ऑर्थोपेडिक उपकरणों, जूते एवं फुटवियर विनिर्माण, लगेज/बैग विनिर्माण, खिलौनों, प्लास्टिक की वस्तुओं, ऑटोमोबाइल साज-सामानों तथा विभिन्न उद्योग खण्डों में होता है । संबद्ध वस्तु को अध्याय 58 के अंतर्गत उप शीर्ष सं0 5806.1000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कई ऐसे प्रकार (आकार) हैं जिनमें संबद्ध वस्तु का उत्पादन एवं बिक्री की जाती है और वे फैब्रिक की चौड़ाई एवं लंबाई के रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं । सामान्य तौर पर इनका आकार 12 मि0मी0 चौड़ाई से 125 मि0मी0 चौड़ाई के बीच होता है और वह लंबाई, जिसमें उत्पाद का दायिज्यिक रूप से उत्पादन और बिक्री होती है, 25 मी0 होती है, हालाँकि ग्राहक की आवश्यकतानुसार उसका उत्पादन किसी भी लंबाई में किया जा सकता है । इसलिए, याचिका में याचिकाकर्ता ने सारे आँकड़ों को 1 मी0 लंबे तथा 25 मि0मी0 चौड़े के बराबर के रूप में परिवर्तित कर दिया है और उसका भार 8.0 ग्राम लिया गया है । वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी उत्पाद के भार को माप की इकाई के रूप में मानने का प्रस्ताव करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद के बारे में जाँच शुरू की जा रही है भले ही जिस वर्गीकरण के तहत उसका आयात किया जा रहा है, वह कुछ भी हो । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

## 2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मै0 र्काई इंडस्ट्रीज लि0, मुंबई द्वारा दायर की गई है । मै0 नैरो इलास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता के अतिरिक्त तीन मुख्य उत्पादक हैं जो भारत में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करते हैं । वे हैं मै0 सिद्धार्थ फिलामेंट्स प्रा0 लि0, सूरत, सिद्धार्थ मैजिक टैप्स प्रा0 लि0, गुजरात एवं मैजिक फास्टेनर्स प्रा0 लि0, रोहतक, हरियाणा । भारतीय उत्पादन के वितरण की जाँच करने के पश्चात् यह देखा गया है कि यद्यपि याचिका को मै0 मैजिक फास्टेनर्स एवं सिद्धार्थ मैजिक टैप्स का समर्थन प्राप्त है, तथापि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । उपरोक्त की जाँच करने के बाद प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हुए याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एक बड़ा उत्पादक है और इसलिए नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग बनता है और वह उपरोक्त नियमावली के नियम 5(3)(क)

### 3. शामिल देश

प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद यह निर्धारित किया है कि हाँगकाँग से होने वाले आयात मात्रात्मक रूप में न्यूनतम से कम हैं और इसलिए उन्हें जांच से बाहर रखा गया है। वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन एवं चीनी ताइपेई (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं।

### 4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि दोनों वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए उपर्युक्त नियम के अर्थ के भीतर, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

### 5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने अमरीका के अपने निर्यातों के लिए ताईवान की एक कम्पनी द्वारा दिए कोटेशन की एक प्रति के अनुसार ताईवान में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है। यद्यपि कोटेशन में दी गई कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं, कारखाना द्वार कीमत परिकलित करने के लिए इनमें समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने ताईवान में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों, वेतन, वित्तीय लागतों, विद्युत लागतों आदि के संबंध में सहायक साक्ष्यों के साथ-साथ उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। चीन जन.गण. के मामले में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था समझा जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का परिकलन अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. तथा चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

### 6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात संबंधी आंकड़ों तथा विभिन्न आयातकों द्वारा किए गए वास्तविक आयातों के साक्ष्यों के आधार पर किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यातक देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए दावा की गई निर्यात कीमत तथा समायोजनों के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

### 7. पाटन मार्जिन

इस प्रकार के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

## 8. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि, आयात कीमतों में गिरावट, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट, निवेश पर कम आय, कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास जैसे मानदंड प्रथम दृष्टया सामूहिक एवं संचयी रूप से यह इंगित करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

## 9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपर्युक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

## 10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 (12 महीने) तक की है।

## 11. सूचना देना

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत सरकार, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं।

उपर्युक्त नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपयोक्ता संगठनों को भी अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

## 12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया

जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### 13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2004

**Subject: Initiation of Anti-dumping Investigations concerning import of Narrow Woven Fabrics originating in or exported from China and Chinese Taipei.**

No. 14/24/2003-DGAD.—M/s. Sky Industries Limited, Mumbai, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Narrow Woven Fabrics originating in or exported from China, Chinese Taipei and Hong Kong and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

### 1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under investigation in the present case is Narrow Woven Fabric having pile weave, made up of man made fibres, used as fastening tape (henceforth referred to also as subject goods). In market parlance, the subject goods are known by various synonyms such as 'hook and look tape fasteners', 'velcro tapes', 'fastening tapes', 'fasteners' etc. Regardless of the nomenclature used, the product under consideration is narrow woven fabric having pile weave. The subject goods are produced in various sizes depending upon specific end use and these are described in terms of peel strength, sheer strength and light fastness. Narrow Woven Fabrics has been defined under the Customs Tariff Act as follows

"Narrow Woven Fabrics means a) woven fabrics of a width not exceeding 30 centimeters whether woven as such or cut from wider pieces, provided with selvages (woven, gummed or otherwise made) on both edges; b) Tubular woven fabrics of a flattened width not

1783 GI/04

exceeding 30 centimeters and c) bias binding with folded edges, of a width when unfolded not exceeding 30 centimeters."

The Authority notes from the above definition that the product under consideration is a narrow woven fabric, as described earlier, which is below 30 centimetres in width. The wide woven fabrics as classified under the various customs classification under chapter 54 are not included in the scope of the investigation. Hook and loop fasteners are generally made from man made fibres (yarns), nylon (nylon 6 and nylon 6.6), polyester etc. The subject goods is a combination of two separate woven tapes, one called the hook tape and other a loop tape, which when placed in contact with other displays excellent fastening properties. The subject goods offers hundreds of potential closure systems (fastening applications) for a wide range of applications. Major uses of subject goods are in industries such as garment industry, leather garments/furnishings, surgical and orthopedic apparatus, shoes and footwear manufacturing, luggage/bag manufacturers, toys, plastic goods, automobile upholstery and various other industry segments. The subject goods are classified under chapter 58 under sub heading No.5806.1000. The petitioner has claimed that there are a number of types (sizes) in which the subject goods are produced and sold and these are differentiated in terms of width and length of the fabric. The sizes typically vary between 12 mm to 125 mm of width and length in which the product is commercially produced and sold is 25 meters though it can be produced in any length depending upon the customer's requirement. In the petition, the petitioner has, therefore, converted entire data in terms of equivalent of 1 meter length and 25 mm of width and weight of the same has been taken as 8.0 grams. The Authority proposes to consider weight of the product as the unit of measurement for the purpose of present investigation.

Investigations are being initiated with respect to product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigations.

## **2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING**

The petition has been filed by M/s Sky Industries Limited, Mumbai. As per the letter received from M/s. Narrow Elastic Manufacturers Association of India, there are three major producers apart from the petitioner who manufacture the subject goods in India. These are M/s. Siddhartha Filaments Private Limited, Surat, Siddhartha Magic Tapes Private Limited, Gujarat and Magic Fasteners Private Limited, Rohtak, Haryana. After examining the details of Indian production, it is seen that the production of the petitioner constitutes a major proportion of

the Indian production though the petition is supported by M/s. Magic Fasteners and Siddhartha Magic Tapes. The Authority after examining the above, determines that the petitioner is a major producer of subject goods in India accounting for a major proportion of the production of the subject goods in India and therefore the petitioner constitutes a domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) and it satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3)(a) of the Rules supra.

### **3. COUNTRIES INVOLVED**

The Authority after preliminary examination has determined that imports from Hong Kong are de-minimus in volume terms and are therefore excluded from investigations. The countries involved in the present investigation are China PR and Chinese Taipei (hereinafter also referred to as subject countries).

### **4. LIKE GOODS**

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, supra.

### **5. NORMAL VALUE**

The petitioner has claimed the normal value of subject goods in Taiwan as per a copy of quotation given by one of Taiwanese Company for their exports to USA. Though the prices given in the quotation is CIF, it has been adjusted to arrive at ex-factory prices. In addition, the petitioner has also constructed normal value based on estimates of cost of production along with the supporting evidences in respect of raw material prices, wages, financing costs, power costs, etc. to arrive at the normal value of subject goods in Taiwan. In case of China PR, the petitioner has claimed that China PR has to be treated as a non-market economy and normal value has to be determined in accordance with the para 7 of Annexure I. The authority notes that there is sufficient evidence of normal value claimed for the subject goods from China PR and Chinese Taipei.

### **6. EXPORT PRICE**

The Petitioner has claimed the export price of subject goods from the subject countries based on the import data provided by the DGCIS and evidence of actual imports made by the various importers. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level. There is sufficient evidence of export price and the adjustments claimed for the subject goods from subject countries.

#### **7. DUMPING MARGIN**

There is, prima facie, evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

#### **8. INJURY AND CAUSAL LINK**

Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in volume of imports from subject countries, decline in the import prices, increase in the market share of imports from subject countries, decline in the market share of the domestic industry, decline in the domestic selling price, low return in investment, price undercutting, price depression and price suppression, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.

#### **9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS**

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

#### **10. PERIOD OF INVESTIGATION**

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> January 2003 to 31<sup>st</sup> December 2003 (12 months).

#### **11. SUBMISSION OF INFORMATION**

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner



prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

## 12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

## 13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. SENGUPTA, Designated Authority

1783 GJ/04